f- मल

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2015

विषयः: मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-199/2014 अलमित्रा एच पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.12.2014 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अलमित्रा एच. पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के संबंध में ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 199/2014 जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से संबंधित है, के संबंध में सुनवाई करते हुए दिनांक 03.12.2014 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं-

"We also direct all State Governments to study the judgment of the Tribunal in the case of Capt. Mall Singh & Ors. vs. Punjab PCB & Ors. - Appeal No. 70 of 2012 on 25th November, 2014, which deals with the methodology and steps that are to be taken by the States/State Boards for collection and disposal of municipal solid waste...."

उक्त अपील संख्या 70/2012 कैप्टेन माल सिंह एंव अन्य बनाम पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में मा. न्यायाधिकरण द्वारा पंजाब सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्य योजना को स्वीकृत करते हुए अन्य बिन्दुओं के साथ निम्नलिखित आदेश/निर्देश दिये गये हैं:-

"(d) Till the time the plants are constructed and become operational, the State Government, Municipal Authorities and the SPCB shall ensure adherence and the implementation of the MSW Rule, 2000. The MSW shall be collected door to door, segregated at the collection point at the dumping site either mechanically or manually. <u>The dumping site shall be maintained properly and in accordance with rules.</u>

e) <u>The pits shall be duly lined; after dumping of the MSW, the same shall be covered with soil as provided under Rules.</u> The authorities concerned will ensure spray of disinfectant on regular intervals.

f) Each site would have boundary wall.

g) The transportation from point of collection to the site shall be done strictly in accordance with rule, <u>in the vehicles which are covered and do not spread MSW enroute.</u>

h) All authorities concerned shall engage <u>appropriate workers forthwith to ensure MSW collection from door to door, segregation, transportation and dumping of MSW</u> at the site appropriately and effectively.

i) In the meanwhile, it will also be ensured by all the authorities that the <u>MSW is not permitted to be littered around or thrown on the road or any parts of the cities.</u>

j) <u>The dustbins of appropriate size shall be provided in every colony</u> to provide incentives to the persons to put Municipal garbage only in to the dustbin and not on the road side etc.

k) The persons who throw the MSW on the road or around their houses should be strictly dealt with by the Municipal authorities and should be punished in accordance with law.

l) On the basis of polluter pays principle, the corporation will charge every household, shop, hotel, or any industrial building to pay specific amount along with the property tax payable for the property, or on monthly basis, whichever is permitted by the concerned authorities. The amount shall be notified and duly publicised before implementing the same. Such payment at the specific rate would be applicable with effect from 1st January, 2015. The amount collected as afore-directed shall only be used for effective collection and disposal of MSW in accordance with the rules and for educating masses in relation to the need for helping bodies/ authorities concerned to collect the MSW in appropriate manner.

m) All authorities particularly, the police is hereby directed to provide due protection and hearing to the Municipal authorities and other administrative authorities in every district to ensure implementation of these directions in adherence to the MSW Rules 2000. "

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओरिजनरल अपील संख्या-70/2012 कैप्टन माल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन करते हुए मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की स्थिति से प्रत्येक माह निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के कियान्वयन में शिथिलता के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का होगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 335(1)/नौ-5-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन का अनुश्रवण करते हुए अद्यतन स्थिति की सूचना संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।